संपादकीय

मधुमेह पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की महासभा में जून 27, 2001 में एक प्रस्ताव अनुमोदित कर विश्व भर का ऐड्स व एच.आई.वी. की महामारी के बारे में आगाह किया। इस प्रस्ताव में इस महामारी के प्रसार रोकने, जागरुकता लाने, शोध पर और धन देने व इस बिमारी से बुरी तरह प्रभावित देशों की मदद देने का संकल्प सदस्य देशों ने किया। विश्व भर में चले जागरुकता अभियान से निश्चित ही इस बिमारी की बढ़ने की गति पर ब्रेक लगे।

आज मधुमेह ऐड्स– एच.आई.वी. से कई गुणा बड़ी महामारी बनकर उभर रही है। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर उसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। लगभग एक दशक में मधुमेही मरीजों की संख्या भारत में दस करोड़ को छूने लगी है। इस बिमारी से उत्पन्न हृदय रोग, किडनी रोग, नेत्र रोग व पैरों के रोगों के लिये हमारी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य तंत्र कतई तैयार नहीं है। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इलाज महँगा होता जा रहा है, डॉक्टर व अस्पतालों की कमी है और ऊपर से जागरुकता के अभाव में पढ़े–लिखे लोग भी जब तक गम्भीर विकार न हो जाये, लापरवाही करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ (International Diabetes Federation) की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) महासभा में एक ऐड्स–एच.आई.वी. की तर्ज पर संकल्प लागू करवाने का प्रस्ताव है। बांग्लादेश ने इस प्रस्ताव का मसविदा तैयार कर 71 देशों का समर्थन प्राप्त कर लिया है। उसके अनुमोदित होने पर मधुमेह पर जागरुकता, शोध व इलाज के लिये सदस्य देश एक साँझा रणनीति बनायेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ को धन उपलब्ध करायेंगे। इस प्रयास से मधुमेह महामारी को रोकने, जागरुकता लाने व इलाज में निश्चित ही सहायता मिलेगी।

● संपादक